

दिनांक-27.05.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:-

- (1) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
- (2) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
- (3) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
- (4) श्री निर्भय कुमार सिंह, अवर सचिव
- (5) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DDC या DPRO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

I. मल्टी पोस्ट ई0वी0एम0 के भण्डारण हेतु वेयर हाउस के चयनोपरान्त आवश्यक उपकरणों, साज-सज्जा एवं मरम्मती के लिए आवश्यक निधि/आवंटन से संबंधित अधियाचना उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थिति:-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि केवल अररिया, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, नवादा, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सारण एवं सीतामढ़ी जिलों द्वारा ही मल्टी पोस्ट ई0वी0एम0 के भण्डारण हेतु आवश्यक निधि/आवंटन से संबंधित अधियाचना विभाग को भेजी गयी है। शेष जिलों के DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि ई0वी0एम0 के रख-रखाव हेतु निधि/आवंटन से संबंधित अधियाचना दो(2) दिनों के अंदर पत्र के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:-बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. पंचायत सरकार भवन में आधार (AADHAAR) सेवा उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थिति:-

विदित हो कि दिनांक-06.05.2026 को आयोजित बैठक में पंचायतों में बचे हुए कार्य को पूर्ण करते हुए दिनांक- 21.05.2026 से 2000 पंचायतों में आधार सेवा

शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परंतु समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1936 पंचायतों में Desktop, 602 पंचायतों में Wired Internet Connection उपलब्ध है। आधार सेवा उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल पर Enroll कराये गये 1904 डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के विरुद्ध मात्र 912 ऑपरेटरों द्वारा ही परीक्षा हेतु पंजीकरण कराया गया है। यह चिन्ताजनक है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर सभी 2000 पंचायतों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का पोर्टल पर Enrollment कराकर प्रशिक्षण कराना तथा परीक्षा हेतु पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

अद्यतन स्थिति तक केवल 414 आधार किट का ही क्रय किया गया है। लक्ष्य को देखते हुए सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अविलंब पंचायत से आधार किट क्रय कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिन पंचायतों में Wired Internet Connection उपलब्ध नहीं है वहां दो दिनों के अंदर Internet Connection install करना सुनिश्चित करेंगे तथा Static IP address को Google Sheet पर उपलब्धता के आधार पर विभाग को सूचित करें। तत्पश्चात विभाग द्वारा उचित निर्णय लेकर संबंधित जिलों को संसूचित किया जाएगा।

(अनुपालन:-बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. सप्तम राज्य वित्त आयोग-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 26 जिलों के 373 प्रखंडों के 5596 पंचायतों के विरुद्ध मात्र 40 पंचायतों के द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर मांगी गयी वांछित सूचना/प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सूचना/प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें ताकि सप्तम राज्य वित्त आयोग को ससमय उपलब्ध करायी जा सके।

(अनुपालन:-बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. मुक्तिधाम, शवदाह-गृह, मृत्यु प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति:-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 7856 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवेदित माह में 1971 अंत्येष्टि की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित अवधि के अंदर 1729 मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत की गयी है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा सभी DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदित माह में किये गये कुल अंत्येष्टियों की जांच कर पोर्टल पर Update करें। साथ ही अंतिम संस्कार हेतु परम्परागत रूप से उपयोग किये जाने वाले सरकारी भूमि का ही सर्वेक्षण किया जाए।

सभी DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि शमशान/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के मृतकों का मृत्यु प्रमाण-पत्र 24 घंटे के अन्दर मृतकों के संबंधितों

लगातार.....

को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं निदेश भी निहित है।

विदित हो कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर मोक्षधाम की समीक्षा की जाती है। निदेशित किया जाता है कि सभी DPRO नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:-बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण एवं क्रियाशीलता की अद्यतन स्थिति:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक-01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु गया जी, पूर्वी चंपारण, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली एवं दरभंगा जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO एवं DDC को निदेशित किया गया कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से लिखित रूप में निर्माण एजेंसी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को सूचित करें तथा एक सप्ताह के अंदर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल 3023 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 2622 पंचायत सरकार भवन संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 108 में बैंक, 2594 में RTPS केन्द्र, 923 में Post Office, 441 में NOFN, 917 में पुस्तकालय एवं 25 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। केवल 661 पंचायत सरकार भवनों में ही सफाई कर्मी-सह-सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 743 पंचायतों के प्राक्कलन के विरुद्ध 617 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति, 523 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 134 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र सभी पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए तथा जिन पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, उन पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।



लगातार.....

(अनुपालन:-सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. पंचायत सचिव के प्रभार संबंधी प्रतिवेदन एवं 15 वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग का दिनांक-8 अप्रैल 2026 से 06 मई 2026 तक पोर्टल पर व्यय की अद्यतन स्थिति:-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 3130 पंचायत सचिवों के विरुद्ध मात्र 686 ही कार्यरत हैं। शेष 2444 पंचायत सचिव हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर गये पंचायत सचिव के स्थान पर 2318 कर्मियों को अतिरिक्त प्रभार दी गयी है। जिले द्वारा मात्र 1194 पंचायत सचिव पर ही आवश्यक कार्रवाई की गयी है, जो चिंताजनक है। निदेश दिया गया कि हड़ताल पर गये संबंधित पंचायत सचिव पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:- बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना:-

(क). मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक-31.03.2026 तक चतुर्थ चरण में सभी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना था परंतु अद्यतन स्थिति तक भागलपुर में मात्र 19%, बेगूसराय में 40%, सहरसा में 41%, मधेपुरा में 40% एवं सारण में 51% सोलर स्ट्रीट लाईट का ही अधिष्ठापन किया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में उक्त जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि एकरारनामा की शर्तों के अनुसार संबंधित एजेंसी पर Penalty लगाकर विभाग को सूचित करें। जिन-जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि दिनांक-31.05.2026 तक शत-प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाए।

चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी द्वारा भागलपुर में 51%, मधेपुरा में 42% ही Material Supply की गयी है। इन जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र संबंधित एजेंसी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख). सभी चरणों को मिलाकर सिवान, पूर्णिया, नवादा, मधेपुरा, औरंगाबाद, जमुई एवं बांका जिलों में अधिष्ठापित लाईटों के विरुद्ध CMS पर Integration का प्रतिशत काफी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर CMS पर 100% Integration करना सुनिश्चित करें।

दिनांक- 06.05.2026 को आयोजित बैठक में सभी DPRO को निदेश दिया गया था कि सोलर स्ट्रीट लाईट की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु दिनांक- 11.05.2026 तक जिला स्तर पर LED Display Pannel लगाकर फोटो विभाग के Whatsapp Group में भेजना सुनिश्चित करेंगे, परंतु 09 जिले यथा दरभंगा, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, नालंदा, नवादा, पश्चिम चंपारण, पटना एवं शिवहर द्वारा LED



लगातार.....

Display Pannel अधिष्ठापित नहीं किया गया है। उक्त जिलों के DDC/DPRO को निदेश दिया गया कि अविलंब LED Display Pannel अधिष्ठापित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग). जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा, जहानाबाद, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर जिलों में सभी चरणों में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, वैशाली, नवादा, औरंगाबाद, पटना, सारण, सहरसा एवं बक्सर जिलों में सभी चरणों में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:-सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार अद्यतन स्थिति :-

S.n	District Name	No. of CWJC	No. of MJC
01	Araria	02	00
02	Arwal	02	00
03	Aurangabad	08	00
04	Banka	00	00
05	Begusarai	05	00
06	Bhagalpur	03	00
07	Bhojpur	01	00
08	Buxar	05	01
09	Darbhanga	11	00
10	East Champaran	09	00
11	Gaya	05	00
12	Gopalganj	05	00
13	Jamui	08	00
14	Jehanabad	03	00
15	Kaimur	00	00
16	Katihar	05	00
17	Khagaria	10	00
18	Kishanganj	03	00
19	Lakhisarai	01	00
20	Madhepura	01	00
21	Madhubani	10	00
22	Munger	04	00
23	Muzaffarpur	09	00
24	Nalanda	01	00
25	Nawada	05	00
26	Patna	10	00
27	Purnia	01	00

28	Rohtas	08	01
29	Saharsa	00	00
30	Samastipur	10	02
31	Saran	06	02
32	Sheikhpura	01	00
33	Sheohar	00	00
34	Sitamarhi	08	01
35	Siwan	04	00
36	Supaul	02	00
37	Vaishali	12	00
38	West Champaran	01	01
Total		179	08

सभी लंबित MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:-सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थिति:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:-

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
01	जिला परिषद्	07.58%
02	पंचायत समिति	15.59%
03	ग्राम पंचायत	8.71%

बक्सर, लखीसराय, दरभंगा, नालंदा, नवादा, अररिया एवं भागलपुर जिलों के जिला परिषद् द्वारा व्यय की गयी राशि काफी कम है। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर यथाशीघ्र व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) षष्ठम राज्य वित्त आयोग:-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:-

षष्ठम राज्य वित्त आयोग		
क्र०सं०	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
01	जिला परिषद्	40.20%
02	पंचायत समिति	73.85%
03	ग्राम पंचायत	74.25%

नवादा, दरभंगा, पटना एवं मधुबनी जिलों के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक

लगातार.....

पदाधिकारी, जिला परिषद् एक माह के अंदर कम से कम 50% का व्यय करना सुनिश्चित करेंगे। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर यथाशीघ्र व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:-सभी जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

X. लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :-

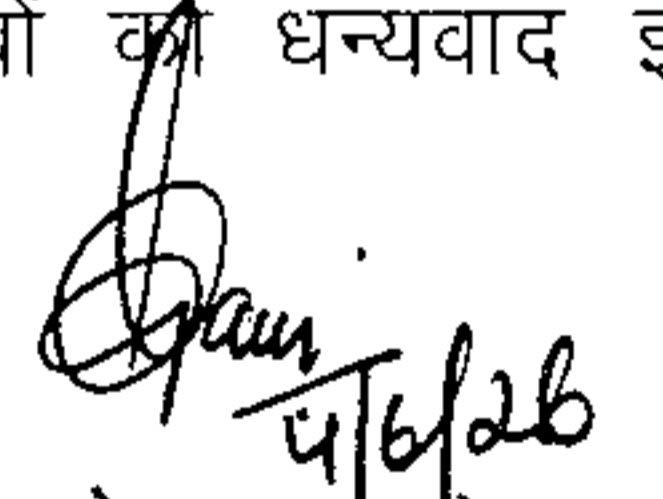
(क) बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

अद्यतन स्थिति तक मई माह में जिलों द्वारा Rs 700 Cr का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा गया है, जो संतोषजनक है। मुजफ्फरपुर, पटना, पश्चिम चंपारण, गया जी एवं सुपौल जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(ख) **Departmental Audit Progress Report(FY: 2024-25)**- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 38 जिला परिषद् के विरुद्ध 26, 533 पंचायत समिति के विरुद्ध 477, 8053 पंचायत के विरुद्ध 7117 एवं 8053 ग्राम कचहरी के विरुद्ध 7289 में ही ऑडिट कार्य पूर्ण किया गया है। निदेश दिया गया कि दिनांक-31.05.2026 तक सभी ऑडिट कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:-सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

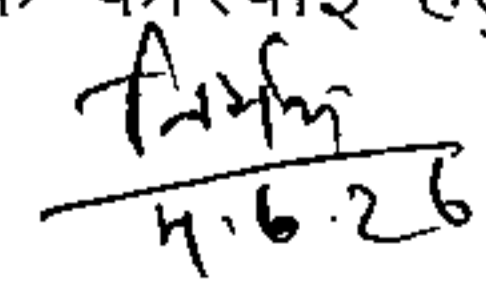
सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(मनोज कुमार)
सचिव

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

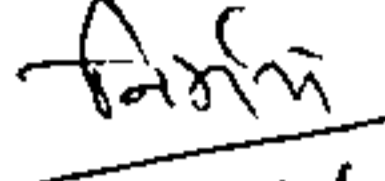
ज्ञापांक:-950/विविध-01-247/2023/8619/...../पं०रा० पटना, दिनांक 05/6/2026

प्रतिलिपि:-बिहार के सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक:-950/विविध-01-247/2023/8619/पं०रा० पटना, दिनांक 05/6/2026

प्रतिलिपि:-सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



4.6.26

(निर्भय कुमार सिंह)

अवर सचिव

ज्ञापांक:-950/विविध-01-247/2023/8619/पं०रा० पटना, दिनांक 05/6/2026

प्रतिलिपि:-आईटीमैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


4.6.26

(निर्भय कुमार सिंह)

अवर सचिव